जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 03 प्रभात जालोर, शुक्रवार 11 अप्रैल, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

विश्व सदमे में है, पहले अमेरिका द्वारा लगाये गये टैरिफ से और फिर टैरिफ प्रक्रिया को अचानक आगे खिसकाने से

इस घटनाक्रम ने ट्रम्प की नीतियों की अनिश्चितता व अव्यवहारिकता पर से पर्दा हटा दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रेल। ट्रंप के टैरिफ ने जब पूरी दुनिया और वित्तीय बाज़ारों को हिलाकर रख दिया है और ट्रंप ने इस नीति के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर नेताओं से लेकर बाज़ार तक सभी को चौंका दिया है।

अब उतनी ही जल्दबाजी में उन्होंने रैसिप्रोकल टैरिफ का टाइम आगे खिसका दिया। उन्होंने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया, जिससे बाज़ारों में थोड़ा उछाल आया। उन्होंने चीन को छोड़कर सभी देशों को टैरिफ में राहत दी।

इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप प्रशासन की पूर्णतया अप्रत्याशित तथा अवास्तविक कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया है। उनके करीबी अधिकारियों, जिसमें अमेरिका के वाणिज्य सचिव भी शामिल हैं, को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। ट्रंप प्रशासन की अनिश्चितता ने एक बार फिर बाज़ार को प्रभावित किया और बाज़ार का उछाल थम गया।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी बहुचर्चित टैरिफ नीति को उन्होंने रोक दिया, क्योंकि यह साफ तौर पर पीछे हटना ही है।

- पर, ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका के ट्रैज़री सैक्रेटरी स्कॉट बैसैंट ने ट्रम्प के निजी निवास पर जाकर, अमेरिका के ''बॉण्ड मार्केट'' की स्थिति से उन्हें अवगत कराया।
- जैसा कि विदित ही है, कोई भी सरकार अपने पुराने ऋण नहीं चुकाती, केवल नये ऋण लेकर, पुराने ऋण की प्रतीकात्मक अदायगी करती है। पर, अगर, सरकार के बॉण्ड्स मार्केट में ढीले पड़ जायें तो बाज़ार से नया ऋण उठाने का क्रम टूट सकता है।
- शायद स्कॉट बैसैंट ने यह स्थिति ट्रम्प के सामने उजागर की और इससे मंदी का दौर (डिप्रैशन) शुरु होने की आशंका जताई।
- 1930 के ''ग्रेट डिप्रैशन'' के दृश्यों को अमेरिका भूला नहीं है और ''डिप्रैशन'' बड़ा भयानक शब्द है अमेरिका वासियों के लिये।
- बैसैंट के संदेश व निष्कर्ष को अमेरिका के जाने-माने उद्योगपतियों व इकॉनमिस्टों ने ट्रम्प को सीधे लगातार फोन कर दोहराया और अन्त में ट्रम्प को अपने टैरिफ लगाने के प्लान को 90 दिन स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा।

ट्रंप ने जोर-शोर से दावा किया था कि उनकी ट्रेड वॉर नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। वे इस नीति को अवश्य ही लागू करेंगे। उन्होंने यह भी डींग मारी थी कि 75 से अधिक देशों ने उनसे विनती की है कि वे कोई समझौता करें और उनके बढ़े हुए टैरिफ से राहत दें।

उन्होंने हमेशा की तरह टैरिफ उपायों को लेकर शेखी बघारी। लेकिन, उनके आंतरिक सर्कल में सभी देशों पर एक साथ इतने कठोर उपाय लागू करने का आत्मविश्वास और भावना अब धीमी होती जा रही थी और अधिक व्यावहारिक सोच सामने आ रही थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी ट्रेज़री सचिव स्कॉट बेसेंट, ट्रंप के निजी निवास पर पहुँचे, ताकि बाज़ार की स्थिति को लेकर उन्हें आगाह कर सकें। उन्होंने ज़ोर दिया कि अमेरिकी ट्रेज़री मार्केट में भारी गिरावट आई है और यही वह धुरी है, जिस पर संघीय सरकार की वित्तीय स्थिति घूमती है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (सीएनएन) ने रिपोर्ट किया कि बुधवार को अमेरिकी संघीय सरकार के बॉन्ड ऑफर को वह प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो सामान्यत: मिलती है।

टैरिफ से उत्पन्न उथल-पुथल के बाद, अमेरिका का सरकारी ऋण खरीदने वाले बड़े निवशकों में अब उतना उत्साह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने रणथम्भौर में टाइगर देखे

सवाई माधोपुर, 10 अप्रैल (निस)। लोकसभा विपक्ष के नेता व कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर रणथम्भौर आए हुए हैं। उन्होंने आज सुबह और शाम की पारी में रणथम्भौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी कर बाघों की अठखेलियां देखीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से बुधवार को सीधे अहमदाबाद से फ्लाइट से जयपुर पहुंचे। जयपुर से सड़क मार्ग से देर रात करीब 10 बजे सवाई माधोपुर के रणथम्भौर पहुंचे। राहुल यहां रणथम्भौर के शेर बाग़ होटल में ठहरे हुए हैं।

- राहुल ने सुबह और शाम दोनों पारी में जंगल का भ्रमण किया।

राहुल गांधी ने पांच सितारा होटल शेरबाग़ में रात्रि विश्राम किया। गुरुवार सुबह और शाम की पारी में उन्होंने रणथम्भौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अठखेलिया देखीं। इस दौरान राहुल गांधी ने बाघिन टी 84 एरोहेड व उसके शावकों की अठखेलियों को अपने कैमरे में भी कैद किया।

राहुल ने रणथंभौर के जोन नंबर दो में फिमेल टाइगर के दीदार किए। बाघिन व शावकों की अठखेलियां देख कर राहुल गांधी खुश हो गए। उल्लेखनीय है कि गांधी परिवार का रणथम्भौर से गहरा लगाव है। राहुल गांधी की बहन और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी अक्सर रणथम्भौर आती रहती हैं।

अन्ततोगत्वा भारत को मिल ही गया तहव्वुर राणा

26/11 के मास्टर माइंड तहव्वुर को एन.आई.ए. ने पालम एयरपोर्ट से हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। तहव्वुर राणा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, को अमेरिका से भारत ला रहा विशेष विमान आज शाम दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर उतरा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तहव्वुर हुसैन राणा को गुरूवार को यहां पहुंचने पर हिरासत में लिया और सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। अब उसे न्यायालय में पेश किया जायेगा। कई वर्षों की लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद यह दिन आया है।

तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। एनआईए ने उसकी तस्वीर जारी की है। वो बैक साइड से नज़र आ रहा है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतज़ाम कर लिए हैं। हालांकि, उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। एनआईए ने आज शाम को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उसने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राणा के प्रत्यर्पण में सफलता हासिल कर ली है।

भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत शुरू की गई कार्यवाही के चलते राणा को अमेरिका में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। राणा ने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते आजमाए, पर उसे सफलता नहीं मिली, आखिरकार उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हो गयी।

- तहव्वुर को भारत ला रहा विमान गुरुवार शाम नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा था।
- तहव्वुर को तिहाड़ जेल के हाई सिक्युरिटी सैल में रखा जाएगा। इसके लिए जरूरी तैयारी कर ली गई है।

वक्तव्य में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई 2023 को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। इसके बाद राणा ने नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में कई मुकदमे दायर किए, जिनमें से सभी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने एक रिट , दो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आपातकालीन आवेदन भी दायर किया, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। भारत द्वारा अंततः अमेरिकी सरकार से वांछित आतंकवादी के लिए आत्मसमर्पण वारंट प्राप्त करने के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की गई।

एनआईए ने स्काई मार्शल, यूएसडीओजे की सक्रिय सहायता से प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी की, इस दौरान, अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों, एनएसजी का भी सहयोग लिया, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मामले को अंजाम तक ले जाने के लिए अमेरिका में अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल किया।

राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाउद गिलानी और नामित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के गुर्गों के साथ-साथ, पाकिस्तान स्थित अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए और 238 से अधिक घायल हुए।

भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत, लश्कर ए तैयबा और एचयूजेआई दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।

गृह मंत्री चेन्नई पहुँचे

उनकी यात्रा का मुख्य मकसद तमिलनाडु के नये प्रदेशाध्यक्ष का चयन है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। तमिलनाडु भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, राज्य में इस पद के लिए दौड़ तेज हो गई है। अब भाजपा की तमिलनाडु इकाई के इस सर्वोच्च पद पर कोई नया व्यक्ति ही आयेगा।

गुरुवार को भाजपा की राज्य एवं चेन्नई इकाइयाँ सक्रिय घटनाक्रम की साक्षी रहीं। दरअसल, केन्द्रीय गृहमंत्री तथा पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राज्य के दौरे पर यहाँ आये थे। उन्होंने राज्य की राजनैतिक स्थिति का आकलन करन के लिये दिन पर राज्य के विभिन्न पार्टी नेताओं के साथ कई मीटिंग कीं। उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल सभी उम्मीदवारों से मुलाकात की।

पार्टी के इस अन्दरुनी मामले के अलावा, ऐसी आशा की जा रही है कि अमित शाह अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन करने के सिलसिले में भी बात करेंगे। ज्ञातव्य है कि अन्नाद्रमुक लोकसभा चुनावों से ठीक पहले गठबंधन से अलग हो गई थी, क्योंकि अन्नामलाई ने जयललिता सहित, अन्नाद्रमुक के शीर्षस्थ नेताओं पर निशाना साधते हुये, पार्टी की तीखी आलोचना की थी।

- अमित शाह ने दिन भर प्रदेश के भाजपा नेताओं से विचार-विमर्श किया, जिसका लक्ष्य राजनीतिक रणनीति तय करना था, अगले वर्ष तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिये।
- इसी क्रम में अमित शाह, अन्नाद्रमुक से चुनावी गठबंधन की योजना को संभवतः स्वीकृति भी देंगे।
- जैसा कि विदित ही है, तमिलनाडु में भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन टूट गया था, प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहने से। अन्नामलाई ने स्वर्गीय जयललिता को भी नहीं बख्शा था।
- दोबारा गठबंधन करने के लिए अन्नाद्रमुक की शर्त थी कि अन्नामलाई की जगह किसी नये व्यक्ति को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाये।

यद्यपि अन्नाद्रमुक ने फिर से गठजोड़ करने की इच्छा के संकेत दिये हैं, लेकिन समझा जाता है कि गठबंधन के लिये उसकी पूर्व शर्तों में से एक शर्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बाल आयोग अध्यक्ष का कार्यभार आईएएस को क्यों सौंपा'

जयपुर, 10 अप्रेल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार आईएएस अधिकारी को सौंपने पर मुख्य सचिव, संयुक्त बाल अधिकारिता सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव और आईएएस कुलदीप रांका को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने

- हाई कोर्ट ने आयोग की सदस्य संगीता गर्ग की याचिका पर नोटिस जारी किये।

यह आदेश आयोग की सदस्य संगीता गर्ग की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सत्यपाल चंदोलिया ने बताया कि संगीता बेनीवाल द्वारा इस्तीफा देने के कारण आयोग अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गत 5 फरवरी को आदेश जारी कर इस पद का अतिरिक्त कार्यभार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुलदीप रांका को सौंप दिया। याचिका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या टैरिफ वॉर के कारण भारत को मजबूरन द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक रिफॉर्म लागू करने पड़ेंगे?

टैरिफ वॉर के कारण अमेरिका का मार्केट शायद भारत के उद्योगपतियों की पहुँच से बाहर हो जायेगा तथा भारत को विश्व में अन्यत्र मार्केट विकसित करने होंगे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रेल। माना जा रहा है कि अमेरिका की नई टैरिफ नीति, विशेष रुप से रैसिप्रोकल टैरिफ की 5 अप्रेल की घोषणा से भारत में सैकण्ड -जनरेशन रिफॉर्म्स (सुधारों) की शुरुआत हो सकती है। सुधारों की पहली बड़ी लहर तीन दशक पहले 1991 में आई थी। टैरिफ और ट्रेड पॉलिसीज़ से अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रणनीतियों में बदलाव आता है, और भारत के सामने, इस तरह के ग्लोबल परिवर्तन की प्रतिक्रिया में सुधारों को तेजी से बढ़ाने का अनोखा मौका है।

चूँकि, अमेरिकी टैरिफ का उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है, इसलिए भारत अपने घरेलू बाज़ार पर अधिक फोकस करने और अपने उद्योगों को मजबूत करने के लिए प्रेरित हो सकता है। इस परिदृश्य में भारत की सरकार, व्यापार करने की सुविधा को बढ़ाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने और व्यवसायों के लिए रैगुलेटरी बोझ को कम करने की दृष्टि से सैकण्ड जनरेशन (दूसरी पीढ़ी के) सुधारों को आगे बढ़ा सकती है। ये प्रयास भारतीय कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे और विदेशी बाज़ारों पर निर्भरता को कम करेंगे। अमेरिका में प्रोटैक्शनिस्ट पॉलिसीज़ (संरक्षणवादी नीतियों) के बढ़ने से भारत अपने पारंपरिक पार्टनरों के अलावा और अन्य लोगों से ट्रेड पार्टनशिप कर सकता है। यदि अमेरिकी बाज़ारों पर निर्भरता अधिक महंगी हो जाती है तो भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ ट्रेड एग्रीमैंट्स तेजी से आगे बढ़ा सकता है। यह बदलाव भारत को अधिक व्यापार -अनुकूल सुधार लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना और व्यापार में गैर -शुल्क बाधाओं को कम करना।

- इस नए मार्केट में सफल होने के लिए भारत को सैकण्ड जनरेशन रिफॉर्म्स लागू करने पड़ेंगे, जैसे, लेबर लॉज़ में लचीलापन, कृषि उत्पाद की श्रंखला को मजबूत करना और ''ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नैस'' को और मजबूत करना। जब तक यह नहीं करेंगे, भारतीय माल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जम नहीं पाएगा।
- ये रिफॉर्म्स शायद कालांतर में धीरे-धीरे भारत में आते, पर, टैरिफ वॉर से उत्पन्न स्थिति ने शायद भारत सरकार से धीरे-धीरे ''सैकण्ड जनरेशन रिफॉर्म्स'' लागू करने का विकल्प छीन लिया है, अब, तुरंत ही ये परिवर्तन करने होंगे।
- जैसा कि विदित ही है, ''फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स'' 1991 में, लगभग तीन दशक पहले लागू हुए थे।

बदलते ग्लोबल ट्रेड परिदृश्य के जवाब में भारत, इलैक्ट्रॉनिक्स, इस्पात और दवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को भी तेज कर सकता है।

इतना ही नहीं, भारत सरकार श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण और टैक्सेशन में गहन सुधारों को आगे बढ़ा सकती है, ताकि भारतीय निर्माण क्षेत्र को अधिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने बांग्लादेश के ट्रक रोके

ढाका/नयी दिल्ली, 10 अप्रैल। भारत ने पश्चिम बंगाल सीमा से सटे बेनापोल लैंड पोर्ट चेक पोस्ट के रास्ते माल के साथ आ रहे बंगलादेश के चार ट्रकों को वापस भेज दिया है। यह कार्रवाई बंगलादेश को दूसरे देश में माल भेजने के लिए दी गयी ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द किये जाने के एक दिन बाद की गयी है। बंगलादेश के टीवी समाचार चैनल बीडी न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार, बंगलादेश के जेसोर जिले में बेनापोल पोर्ट के उप निदेशक रशीदुल साजिब नजीर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मंगलवार को ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने के कारण पेट्रापोल कस्टम्स (भारतीय पक्ष) ने तीसरे देश के माल को अपने सीमा से ले जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

- ट्रांज़िट सुविधा वापस लेने का आदेश जारी होने के आगले दिन यह कार्यवाही की गई।

'मोदी सरकार बेवजह झूठी वाहवाही ले रही है तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिये'

कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम् ने दावा किया कि राणा को भारत लाने में मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इस सफल ऑपरेशन का श्रेय, यूपीए सरकार द्वारा चुपचाप कूटनीतिक प्रयास जारी रखने को देना चाहिये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रेल। कांग्रेस ने 26/11 के आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की मोदी सरकार की कोशिशों की आलोचना की और कहा कि राणा को भारत लाने में एक लम्बी प्रक्रिया निहित है।

पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम् ने कहा, 10 अप्रैल 2025 को राणा का भारत में प्रत्यर्पण हो गया है। पर इसके पीछे की पूरी कहानी लोगों को बताई जानी चाहिए।

एक लिखित बयान में चिदंबरम् ने कहा, हालांकि मोदी सरकार राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पर, सच इससे भी कहीं बड़ा है। यह प्रत्यर्पण तकरीबन 15 साल के अथक कूटनीतिक, कानूनी व गुप्तचर प्रयासों का परिणाम है, जिसकी शुरुआत यू.पी.ए. सरकार ने की थी।

- चिदंबरम् ने कहा, क्योंकि मोदी सरकार राणा को भारत लाने के लिये बार-बार अपनी पीठ ठोक रही है, इस ऑपरेशन की सच्ची कहानी सार्वजनिक करना आवश्यक है।
- चिदंबरम् ने पूरी ''कहानी' सुनाते हुए बताया कि, तत्कालीन विदेश मंत्री, सलमान खुर्शीद, विदेश सचिव रंजन मथाई ने हैडली व राणा को भारत भेजने के लिए अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन व अण्डर सैक्रेटरी वेण्डी शरमन से लगातार संपर्क व दबाव रखा था। जिसके कारण हैडली को 35 साल की सजा व राणा को भी अमेरिका में कैद रखने के आदेश निकले थे।
- इसके बाद भी कई अड़चनें आईं, पर, अमेरिका में भारत की राजदूत निरुपमा राव की भूमिका बहुत सराहनीय रही।
- अतः चिदंबरम् द्वारा प्रस्तुत कहानी के अनुसार, राणा को भारत लाने के श्रेय की असली हकदार यूपीए सरकार की कूटनीति है, न कि मोदी सरकार के प्रयास।

पूर्व गृह मंत्रीने कहा, प्रक्रिया की शुरुआत 11 नवम्बर 2009 को हुई थी, जब एन.आई.ए. ने दिल्ली में डेविड कोलमॅन हैडली (अमेरिकन नागरिक) और तहव्वुर राणा (मैनडियन नागरिक) व अन्य, जो 26/11 के षडयंत्र में शामिल थे, के खिलाफ केस दर्ज किया था।

उसी माह कैनडा के विदेश मंत्री ने भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग की पुष्टि की, जिसका श्रेय यूपीए सरकार की प्रभावशाली विदेश नीति को जाता है। चिदंबरम् ने बताया, एफ.बी.आई. ने 2 जून 2009 में तहव्वुर राणा को कोपनहैगेन में तैयबा की एक साजिश में सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि राणा को कोर्ट ने जून 2011 में 26/11 में प्रत्यक्ष लिप्तता से बरी कर दिया था, पर अन्य आतंकी कृत्यों के लिए उसे आरोपी ठहराया गया और 14 साल की जेल हुई। यूपीए सरकार ने 26/11 की साजिश के आरोपों से उसे बरी किए जाने पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त की और कूटनीतिक दबाव बनाए रखा।

चिदंबरम् ने कहा, कानूनी झटके के बाद भी, यूपीए सरकार ने कूटनीति के कानूनी तंत्र के जरिए दबाव बनाए रखा। एक एलएटी के तहत परस्पर कानूनी सहयोग के फ्रेम वर्क के आधार पर एन.आई.ए. की तीन सदस्यीय टीम ने वर्ष 2011के अंत में तहव्वुर राणा से पूछताछ की थी। अमेरिका की सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण सबूत दिए, जो दिसम्बर 2011 में प्रस्तुत एन.आई.ए. की चार्जशीट का अंग बन गए। यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लाल किले और जामा मस्जिद पर बम की धमकी

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल, दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किले और जामा मस्जिद को निशाना बनाकर बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ही मौके पर पहुंच कर गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, जांच में कुछ भी नहीं मिला और ये धमकी फर्जी साबित हुई है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने गुरुवार को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा- "हमने घटनास्थल पर दमकल का एक वाहन भेजा और वहां गहन तलाशी ली।

- पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुछ नहीं मिला। धमकी फर्जी साबित हुई।